महाराष्ट्र की शुगर मिलों ने किसानों से रेवेन्यू शेयरिंग पर लाचारी जताई

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र में चीनी की कीमत गिरकर 29.40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। मिल मालिकों ने भी कीमतों में सुस्ती की शिकायत की है। मिल मालिकों के एक ग्रुप ने किसानों के साथ 70:30 के रेशियो में आमदनी में बंटवारे की शर्त पूरी करने में भी असमर्थता जताई है और इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के प्रेसिडेंट टी एस रेड्डी ने कहा, 'चीनी की कीमतें हर जगह गिर रही हैं। चीनी मिले गन्ने के भुगतान को लेकर दबाव में आ गई हैं।' बिक्री में गिरावट के बाद मिलर्स गन्ने के भुगतान को लेकर दबाव में हैं। लोन देने वाले बैंकों ने चीनी की वैल्यू घटा दी है, इससे गन्ने के अग्रिम भुगतान के लिए कम रकम उपलब्ध है। इससे उन मिलों का मार्जिन कम हो गया, जिन्होंने बैंक के भरोसे भुगतान का वादा किया था। वहीं, महाराष्ट्र के मिल मालिकों ने अलग कदम उठाते हुए चीनी की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद में 10 दिनों के बिक्री बंद कर दी थी। हालांकि, दोबारा बिक्री शुरू करने के बाद कीमत तेजी से गिरने लगी। पिछले एक हफ्ते में दाम 1 रुपया प्रति किलो तक कम हुआ है।

चीनी की बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, जबकि मिल मालिक इसकी बिक्री के लिए बेताब हैं

शुगर ब्रोकर अभिजीत घोरपडे ने बताया, 'दिसंबर तक चीनी का दाम पहले ही 5 रुपये प्रति किलो तक गिर गया था। अभी चीनी की बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है। वहीं, मिल मालिक स्टॉक निकालने के लिए बेताब हैं।' चीनी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट मराठवाड़ा क्षेत्र में आई है। यहां चीनी का दाम 29.40 रुपये प्रति किलो तक आ गया है। इंडस्ट्री को डर है कि चीनी की कीमतों में गिरावट तब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार कुछ नीतिगत कदम नहीं उठाती है। सस्वाद माली शुगर फैक्टरी के चेयरमैन राजेंद्र गिरमे ने कहा, 'अगर स्थिति ऐसी ही रही और सरकार ने दखल नहीं दिया तो गन्ने का भुगतान करने में काफी मुश्किल होगी।' मिलर्स भी सुस्त बिक्री की समस्या का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तुलना में समस्या यह उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जहां इस साल रिकॉर्ड प्रॉडक्शन होने वाला है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 16 जनवरी तक राज्य में चीनी उत्पादन में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल की इसी अवधि में राज्य में 38.15 लाख टन का प्रॉडक्शन हुआ था, जबकि इस साल यह 44.48 लाख टन तक पहुंच गया है। यूपी के किसानों को मिलने वाला गन्ना भुगतान भी बढ़ा है। इस साल चीनी मिलों ने किसानों को 9,237 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 6519 करोड़ रुपये था। बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया, 'कीमतों के बारे कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसा लगता है कि वे आगे भी सुस्त ही रहेंगी।'

The Economic Times
18-1-18